



GENERAL STUDIES (Test-3)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)-M-GSM (M-I)-2203

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Gunpat Ram Yadav

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): _____

Reg. Number: _____

Center & Date: _____

UPSC Roll No. (If allotted): _____

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

Feedback

- | | |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता) | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता) |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता) | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह) |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |

1. विद्युत क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इन चुनौतियों के समाधान के कुछ उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10
- Highlight the major structural challenges ailing the power sector. Suggest some measures to overcome these challenges. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

विगत दशकों में भारत ने विद्युत ऊर्जा में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। आर्थिक वर्ष 2020-21 के अनुसार वर्तमान विद्युत स्थापित क्षमता लगभग 400GW है। जिलों से करीब 25% हिस्सा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का है।

विद्युत क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ

1. विद्युत ऊर्जा प्रबंधन में कठिनाई
2. विद्युत पारेक्षण में क्षति उच्च
3. दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन संबंधी आधारभूत ढाँचे का अभाव
4. विद्युत वितरण कम्पनियों व राज्य सरकारों के बीच समन्वय में कमी आदि।

युनैस्को हे निपटने के उपाय

- ⇒ अधिक हे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाई जानी चाहिए।
- ⇒ P-P-P मॉडल को बेहतर तरीके से लागू
- ⇒ ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा।
- ⇒ दुर्गम क्षेत्रों में वहाँ की भौगोलिक दशाओं के अनुरूप वैकल्पिक तरीके अपनाये जाने चाहिए।

भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाकर देश की तरक्की को गति दी जा सकती है। उपरोक्त युनैस्को के दूर कर तथा 2030 तक के 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर देश में ऊर्जा समानता बढ़ा सकते हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2. "भारत में आजादी मिलने के बाद से खंडित भूमि जोत एक मुख्य समस्या बनी हुई है।" कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिये।
"Fragmented landholding has been an issue since India gained independence." Examine its impact on the agriculture sector. (150 शब्द) 10
(150 words) 10

आजादी पूर्व प्रति व्यक्ति औसत जोत आकार करीब 2 हेक्टर था, जो वर्तमान में 0.8 है. यह गिरा है।

औपनिवेशिक भारत में ही देश में भू वितरण तथा स्यासित्व का अधिकार समाप्त नहीं था, इसीलिए स्वतंत्र उपरान्त "भूमि की हदबन्दी" जैसे उपाय किए गए, परन्तु वांछित परिणाम नहीं मिल सके।

आज भी 85% भारतीय किसान वा लघु या सीमान्त श्रेणी में आते हैं, जिले कृषि क्षेत्र में निम्न प्रभाव दिखाई दे रहे हैं -

- (1) 50% से अधिक किसानों के पाल 0.5 है. भूमि ही उपलब्ध है तथा यह भी कई दुर्गमों में विभाजित

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1

- (2) छोटे-छोटे मूखण्डों पर कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से फायदे में नहीं रह जाते।
- (3) परिवारों के विघटन तथा जमीन के स्वाधिन्य के नामान्तरण के चलते कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है।
- (4) लघु कृषकों को बड़े मू-स्वामियों के कृषि मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजदूर होना पड़ता है।

इस प्रकार कृषि क्षेत्र में लघु मूखण्डों के चलते कई प्रश्न उत्पन्न देखे जा रहे हैं। बेहतर भूमि सुधारों तथा मूखण्डों के एकीकरण द्वारा समस्या को सुलझा लेना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. वैश्विक आपूर्ति एकीकरण में भारत में एम.एस.एम.ई. के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं? इन समस्याओं के समाधान में सरकारी हस्तक्षेप कैसे उपयोगी रहे हैं? (150 शब्द) 10
What are the various challenges faced by MSME's in India in global supply integration. How have government interventions been useful in addressing the issues? (150 words) 10

एम.एस.एम.ई. अर्थात् सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम स्तर के वे उद्यम, जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा में होती है। वर्तमान में MSME क्षेत्र GDP में लगभग 30% तथा निर्यात में 43% प्रतिशत का योगदान दे रहा है, तथा 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

MSME के लम्बा चुनौतियाँ

- ⇒ निवेश तथा प्रशिक्षण की
- ⇒ आधारभूत ढाँचे की; जैसे- कोल्ड स्टोरेज
- ⇒ विपणन व निर्यात में समर्थता
- =) उत्पन्न गुणवत्ता
- =) कौशल व प्रशिक्षण संबंधी आदि।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

युनैलियो है निपटने हेतु सरकारी प्रयास

⇒ 'उधम पोर्टल' के माध्यम से व्यापार या उद्योग शुरू करने संबंधी सहायता

⇒ 'स्टैंड अप इंडिया' के माध्यम से विभिन्न संबंधी युनैलियो को दूर।

⇒ परन्तु एवं सेवा नियति पर शुल्क संबंधी लाभ देकर

⇒ 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत प्रशिक्षण देकर।

⇒ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत इनक्यूबेशन सेंटर खोलकर, आदि।

अतः MSME क्षेत्रक देश की तरफकी की रीड़ है, इसे मजबूत करके भारत आने वाले दशक में विकसित राष्ट्रों की लूची में गाम दर्ज करवा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

4. भारत में कुपोषण को दूर करने में फूड फोर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Food fortification can play a crucial role in addressing malnutrition in India. Examine. (150 words) 10

शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण है। तथा कुपोषण को दूर करने हेतु खाद्य पदार्थों में जरूर से जरूरी पोषक तत्वों (आयरन, आयोडीन, विटामिन) को मिलाकर फूड फोर्टिफिकेशन है।

कुपोषण को दूर करने में फूड फोर्टिफिकेशन की भूमिका

⇒ राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत तथा 'मिड डे मील' योजनान्तर्गत सरकार अच्छे के खाधान (चावल, गेहूँ, दाल आदि) में जरूरी पोषक तत्वों को मिलाकर अच्छा प्रयास कर रही है।

⇒ दूध में भी फोर्टिफिकेशन हो सकता है, तथा खाद्य तेलों में भी।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हालांकि अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्य खाद्यान्न वितरण में फूड फोर्टिफिकेशन की भी अति आवश्यकता है।

वर्तमान में 65% से अधिक महिलाएं एवं बच्चियां रक्ताल्पता (एनीमिया) की शिकार हैं, हालांकि सरकार फोर्टिफाइड टेबलेट तथा अन्य आयरन तथा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के माध्यम से प्रभाव कर रही है; परन्तु सरकार है मोटे अनाजों, दूध तथा खाद्य तेलों का पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड करने की।

SDG-2.0 को प्राप्त करने तथा देश के मानव संसाधन को स्वस्थ बनाने के लिए उपरोक्त प्रयासों को तीव्र करने की जरूरत है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

5. आदेशात्मक नियोजन से आप क्या समझते हैं? यह निर्देशात्मक नियोजन से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द) 10
What do you understand by Imperative Planning? How is it different from Indicative planning? (150 words) 10

नियोजन (Planning) से तात्पर्य है, किन्हीं विशेष उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ना।

आदेशात्मक नियोजन में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आदेश के रूप में कार्यनीति व कार्यक्रमों को संबोधित किया जाता है, तथा कर्म क्रियामुक्त किया जाता है।

यह निर्देशात्मक नियोजन से निम्न प्रकार से भिन्न है -

निर्देशात्मक नियोजन में क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्रोतों के निर्देशों का

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

का पालन किया जाता है।

उदाहरण के लिए - द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पी.सी. मटालनोविल के दिशानिर्देशन में विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन हुआ!

जबकि आदेशात्मक नियोजन में एक उच्चतम स्तर के प्राथमिक द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आदेश दे दिया जाता है, यह नहीं पता होता कि कैसे करना है तथा किन आधारों को ध्यान में रखकर नियोजन करना है।

इस प्रकार दोनों ही नियोजन के प्रकार हैं, पर मूलभूत भिन्नता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

6. भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कृषि क्षेत्र को सब्सिडी देने के बजाय कृषि में अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
India should be biased toward funding R&D in agriculture rather than giving subsidies to agriculture sector to ensure food security. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

परिधान में भारत में दी जाने वाली सभी सब्सिडियों में "खाद्य सखिलडी" वर्गीकृत है, पर यह सिर्फ किलानों को ही नहीं, परन्तु खाद्यान्न प्राप्त करने वाली लगभग 80 करोड़ आबादी को लाभ प्रदान कर रही है। कृषकों को इतना मात्र एक हिस्सा कई रूपों में प्राप्त होता है।

यह कृषि सखिलडी कई किलानों को अच्छा सहारा प्रदान कर रही है, परन्तु इतना अधिकारी लाभ बड़े किलानों ही उठाते हैं।

चूंकि कृषकों को दी जा रही सखिलडी उन्हें तात्कालिक सहयोग तो प्रदान कर रही है, परन्तु उनकी क्षमताओं में विकास नहीं कर पा रही।

ऐसे में कृषि में नवाचार तथा अनुसंधान में वित्त पोषण निम्न प्रकार से किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है -

- (1) कृषि में नवाचार
- (2) नई कृषि के जलवायु अनुकूल बीजों को बनाकर
- (3) जल गहन फसलों के विकल्प खोजकर
- (4) लघु जेत खण्डों के लिए लाभदायी कृषि तकनीकें लाकर।

इस प्रकार सरकार की सख्खी का एक हिस्सा उपरोक्त कृषि अनुसंधानों व नवाचारों के रूप में प्रदान करके किसानों को सहायी रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

7. जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के युग में, सूक्ष्म सिंचाई फसल की उपज बढ़ाने और पानी की आवश्यकताओं को कम करने में मदद कर सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
- In the age of climate change and water scarcity, micro-irrigation can help increase crop yield and decrease water requirements. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सूक्ष्म सिंचाई कृषि सिंचाई की वह विधि

है जिसमें नहर के रूप में खुली सिंचाई न करके पौधों की आवश्यकता अनुसार छंद-छंद अथवा फंक्वारा के माध्यम से सिंचाई करना।

सूक्ष्म सिंचाई जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई है।

वे किसान जिनके खेतों में भूजल की मात्रा अत्यंत कम है, वे पानी का महज छिड़काव करने वाली 'स्प्रिंकलर' अथवा ड्रिप इरिगेशन तकनीकें अपनाकर

अपना पेट पाल रहे हैं, अन्यथा खेती का विकल्प त्यागना पड़ता।

⇒ सूक्ष्म सिंचाई ने जल अति दोहन को कम किया है।

⇒ जनता को जागरूक किया है।

⇒ जिन क्षेत्रों में अभी पानी उपलब्ध है, वे क्षेत्र भी अब सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाकर जल अचत कर संधारणीय कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं।

परन्तु अभी भी सूक्ष्म सिंचाई और के मुँह से जीरा है। उन किसानों को भी सक्षम बनाना होगा, जिनके खेतों में इतना पानी भी नहीं बचा है कि वे सूक्ष्म सिंचाई द्वारा भी फसल उत्पादन कर सकें।

इसके लिए वर्षाजल संरक्षण करके, उल्लेख "ट्रिप इरिगेशन" करवाने हेतु किसानों को मदद की जानी चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

8. फसल विविधीकरण को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों के लिये उच्च आय को बढ़ावा देने के लिये एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

Crop diversification can be used as a tool to promote sustainable agriculture, reduction in import dependence and higher incomes for the farmers. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

फसल विविधीकरण है वास्तव में एक ही खेत में तरह-तरह की फसलें उगाना, न कि हर बार एक ही प्रकार की फसलों को बुवाई।

फसल विविधीकरण के लाभ

- ⇒ मृदा संरक्षण
- ⇒ मृदा उर्वरता में वृद्धि
- ⇒ खरपतवारों में कमी
- ⇒ कीट प्रकोप से सुरक्षा
- ⇒ फसल नष्ट होने के खतरों से सुरक्षा

⇒ आय के एक वैकल्पिक स्रोत का होना, जब एक फसल में कीट प्रकोप हो जाये तब।

कृषि के वाणिज्यीकरण जे कृषि विविधिकरण को कम किया है, अतः कृषि विविधिकरण बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए —

- ⇒ किसान विज्ञान केन्द्रों (KVK) में कृषकों को प्रशिक्षण मिले
- ⇒ कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों के विपणन हेतु संरचनात्मक सुधार हो।
- ⇒ खरी या अधिक ल अधिक फसलों को MSP-न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाये।

— इस प्रकार कृषि विविधिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अद्वयी सुधार व शान-प्रशिक्षण करने होंगे, ताकि देश का कृषि क्षेत्र सुरक्षित व आत्म-निर्भर होगा, जो पूरा देश आत्मनिर्भर हो सकेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

9. दोहरे घाटे (Twin Deficit) की अवधारणा की व्याख्या कीजिये? भारत वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दोहरे घाटे की चुनौती को फिर से उभरती चुनौती से कैसे निपट सकता है। (150 शब्द) 10
- Explain the concept of twin deficit? How can India address the re-emerging challenge of twin deficit challenge in current global scenario. (150 words) 10

दोहरे घाटे से तात्पर्य है, देश की वडी विनिर्माण कंपनियों के साथ-साथ देश के विदेशी व्यापार में भी धारा होगा।

दोहरा घाटा देश की अर्थव्यवस्था तथा बैंकों के लिए खतरनाक लाइन हो सकता है।

→ इससे न केवल बैंकों का NPA बढ़ता है, बल्कि विदेशी मुद्रा भण्डार में भी कमी लाता है।

निपटने के उपाय

1. देश के प्राथमिक क्षेत्र यथा कृषि, खनिज आदि के साथ-साथ बड़े विनिर्माण उद्योगों के आर्थिक स्वास्थ्य की नियमित जाँच होनी रहे, तथा जरूरी मदद होनी रहे।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

2. निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार

3. निरति बाधाओं को दूर करने में प्रयास

4. 'इज ऑफ इजिंग बिजनेस' के मानकों में निरंतर सुधार

5. बैंक धोरणों को रोकने के लिए होश रणनीतिक कदम, आदि

इस प्रकार उपरोक्त उपाय अपनाकर देश दोहरे धाटे की समस्या से न केवल बच सकता है, बल्कि ऐसी वैश्विक समस्या के होने पर भजद्वी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

10.

महामारी और आसन्न मंदी के मद्देनजर, राज्यों को राजस्व की कमी के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

(150 शब्द) 10

In the wake of pandemic and looming recession, states are facing the issue of a revenue shortfall. In this regard how can the principle of fiscal federalism be ensured?

(150 words) 10

महामारी (कोविड-19) तथा उल्लेखित मंदी ने निम्न कारणों से राज्यों के राजस्व का मुद्दा खड़ा कर दिया -

(1) केन्द्र सरकार की बढ़ी हुई सवलियाँ

(2) स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक खर्च होने से केन्द्र सरकार का राजस्व धारा बढ़ना।

(3) केन्द्र सहित राज्यों को राजस्व प्राप्ति में कमी। आदि

(4) उपरोक्त वजह से राज्यों को केंद्रीय आर्थिक संकट में भी कम राशि प्राप्त हुई। ऐसे में कुछ राज्यों ने

केन्द्र सरकार पर "राजकोषीय संघवाद" को क्षीण करने के आरोप लगाए हैं -

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

राजकोषीय संघवाद से नात्पर्य है, वित्तीय मामलों में केन्द्र तथा अन्य सभी सहभागी सरकारें (राज्य तथा स्थानीय) विचार विमर्श कर के उचित निर्णय लें;

उदा. - GST का प्रबंधन

अतः राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने के लिए -

- (1) अन्तर राज्यीय परिषद के माध्यम से वित्तीय मुद्दों पर विचार हो।
- (2) स्थानीय सरकारों व आवश्यकता के आधारों को शार्वजनिक कर पारदर्शिता वरीक से वित्त आवंटन
- (3) GST परिषद तथा नीति आयोग द्वारा औचित्यपूर्ण सुझाव, आदि

इस तरह मौजूदा हालातों में न केवल राष्ट्रीय एकता व अखण्डता एक मुख्य प्रश्न है, बल्कि देश का समतुल्य विकास भी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

11.

समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Increasing Female Labour Force Participation in India is crucial to promote inclusive growth and achieve the Sustainable Development Goals. Discuss the ways in which it can be increased. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

समावेशी विकास से अर्थ है, प्रत्येक वर्ग का विकास सुनिश्चित हो।

सतत विकास लक्ष्यों से अर्थ उन 17 SDG

से है, जिन्हें इस प्रकार से 2030 तक प्राप्त करना है, ताकि विकास की प्रक्रिया धारणीय हो तथा आगे वाली पीढ़ियों तक लाभ मिलता रहे।

SDG प्राप्ति में महिला श्रम बल भागीदारी

- 0 बी हुई महिला श्रम बल भागीदारी विकास को बढ़ा करेगी।
- महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होकर स्वास्थ्य व पोषण समस्याओं को दूर करेगी।

⇒ महिलाएँ शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक व पथकिरण के प्रति सेवक शील होंगी।

⇒ जीने के पानी तथा स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की तरफ ध्यान दिया जा सकेगा।

⇒ एक महिला सशक्त होगी, जो वह पूरे परिवार को गरीबी से निजात दिला सकती है, ऊर्जा

इस प्रकार धारणीय विकास तथा सतत विकास लक्ष्यों में बड़ा ड्रोक महिला बल आगोदारी दर संश्लेषण करेगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

12. संसाधनों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और बड़ा घरेलू बाजार होने के बावजूद, भारत में खाद्य प्रसंस्करण पिछड़ा हुआ है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having competitive advantage over resource endowments and large domestic market, food processing in India lags behind. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

खाद्य प्रसंस्करण से अर्थ है, कच्चे खाद्य पदार्थों व फसलों को मशीनों द्वारा प्रसंस्करित करके बिक्री योग्य गुणवत्ता युक्त, अधिक उच्च के भोज्य पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया।

भारत बड़ा घरेलू बाजार है, परन्तु खाद्य प्रसंस्करण के पिछड़ने के निम्न कारण हैं: —

- (1) निवेश में कमी
- (2) आधारभूत ढांचे का अभाव, जैसे परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, ...

(3) "भेगा फूड पार्क" जैसी योजनाओं का धीमा क्रियान्वयन। पिछले 13 वर्षों में कभी तक केवल 27 ही लुचार्स काफ करना शुरू किये हैं।

(4) भूमि अधिग्रहण समस्याएँ

(5) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की भारत में कम माँग।

(6) ~~भविष्य~~

इस तरह कई कारण हैं, जिनकी वजह से भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक कभी भी पिछड़ा हुआ है।

अतः इसे दूर करने के लिए निम्न उपाय —

- (1) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

में लेनी चाहिए।

(2) सस्ते ऋण तथा सब्सिडी

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

(4) डेरी व्यवसायियों तथा दुग्ध उत्पादकों हेतु उचित प्रोत्साहन आदि।

स्वास्थ्य प्रवर्धन से असीम संभावनाएँ हैं। भारत में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि यह रूढ़ियों की आघ को भी तोड़ने करने में सहयोग करेगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

13.

हाल के वर्षों में भारत की गिग इकॉनमी में भारी उछाल आया है। हालाँकि, गिग इकॉनमी में महिलाओं के प्रवेश में संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं। विश्लेषण कीजिये।
India's gig economy has witnessed an enormous surge in recent years. However, there remain structural barriers to women's entry into the gig economy. Analyse.

(250 शब्द) 15

(250 words) 15

गिग इकॉनमी से तात्पर्य है, "बिना किसी

नियंत्रण के अपने दिसाब से प्रोजेक्ट आधारित व स्वयंयानुसूल कार्य करना।"

उदा. - जोपरी, ओला-उबेर आदि में

हाल ही के वर्षों में विशेषकर कोरोना के बाद से "गिग इकॉनमी" में उछाल आया है, क्योंकि -

(1) कार्य स्वतंत्रता मिलती है।

(2) युवाओं को आकर्षित करता है।

(3) नियोजकों का खर्च भी कम होता है।

(4) एक ही समय में दो या तीन आसनों - अलग-अलग संस्थाओं के

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

साथ जुड़ने का मौका मिलता है।

हालांकि 'गिग इकॉनमी' में महिला भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जिसकी निम्न वजह हैं—

- (1) जाँच की सुरक्षा नहीं
- (2) सरकारी नौकरी अथवा नियमित नौकरी को वरीयता देना
- (3) लिंग आधारित भेद भाव
- (4) उचित तनखाह न मिलना
- (5) काम पर आने-जाने हेतु परिवहन की समस्या।
- (6) घर संभालने की जिम्मेदारी आदि।

इस प्रकार महिला भागीदारी में अनेक समस्याएँ तो हैं कि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

साथ कुछ 'गिग इकॉनमी' की

वैकल्पिक विकल्पों भी हैं, जैसे—

- ⇒ कार्य की प्रकृति: उदाहरण: महिलाएँ ओला-उबेर या जोमेटो-दिल्ली मैली सैंडिथाको के साथ ड्राइवर जैसे काम करने में डिजिटल मदद करती हैं।
- ⇒ कार्य में समय प्रबंधन: अधिकांश कार्य किसी विशेष समय न होकर दिन के 24 घंटों में कभी भी हो सकते हैं, ऐसे में समय प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है।

हालांकि बड़े कॉर्पोरेट के साथ प्रोजेक्ट आधारित उच्च कोटी के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो अच्छी बात है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

14.

“पीएम गति शक्ति योजना में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये भारतीय बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता है।” समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

“PM GATI SHAKTI has the potential to transform Indian infrastructure and logistics to compete with the world's leading economies”. Critically analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

पी.एम. गतिशक्ति योजना देश के

परिवहन क्षेत्र को में आधुनिक परिवर्तन करने की योजना है, जिसके उच्च गति की माल वाहक रेल तथा सड़क गलियारे बनाने के प्रावधान हैं।

यह एक उच्च निवेश प्रोजेक्ट है, जो देश में परिवहन जैसे लॉजिस्टिक सुधारों के माध्यम से निम्न प्रकार से अर्थव्यवस्था को फायदा करेगा —

- (1) बन्दरगाहों से सम्पर्क
- (2) माल परिवहन में समय की बचत।

(3) परिवहन लागत में कमी।

(4) मल्टी मॉडल माल पारगमन गलियारे

(5) निर्यात में तेजी

(6) खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र को भी सहयोग मिलेगा।



• दृष्टि बंदरगाह
- परिवहन गलियारे

परन्तु PM गतिशक्ति योजना के लक्ष्य कुछ चुनौतियाँ भी हैं —

- (1) निवेश के लिए बड़ी राशि
- (2) P-P-P मॉडल के तहत निजी भागीदारों की इच्छा
- (3) योजना क्रियान्वयन में कई राजनीतिक व्यवधान
- (4) भूमि अधिग्रहण में समस्याएँ

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

5. पर्यावरणीय मुद्दे तथा हड़तालें

6. विस्थापन तथा पुनर्वासन संवेदनशीलता।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पी.एन. गतिशक्ति एक महत्वाकांक्षी योजना है, पर साथ ही उपरोक्त मुद्दों को भी समझ रहते सुझावना जरूरी है, तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना में पर्यावरणीय प्रभाव का काल को ध्यान में रखा जाए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

15.

विभिन्न प्रकार के निवेश मॉडलों की चर्चा कीजिये। पी.पी.पी. (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिये।
Discuss the distinct types of investment models. Highlight the issues with the PPP (Public Private Partnership) model.

(250 शब्द) 15

(250 words) 15

भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में आर्थिक विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

उदायीकरण के बाद निवेश में काफी वृद्धि हुई परन्तु अभी भी यह आवश्यकता अनुसार नहीं है। इसके लिए FDI तथा FII दोनों ही माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सूचकांक में सुधार की महती आवश्यकता है।

निवेश मॉडल

निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए निवेश के निम्न मॉडल हैं—

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

① EPC : इंजिनियरिंग - प्रक्योर - कंस्ट्रक्टर

इस मॉडल में तकनीकी भागीदारी के साथ-साथ कानूनी जिम्मेदारी भी निजी कंपनी की होती है, तथा निजी & भागीदार ही निम्नलिखित सामग्री की खरीद करता है।

⇒ इसके लिए सरकार भुगतान करती है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

② HAM : हाइड्रिड एन्युटी मॉडल

इसमें योजना में निधि निवेश निजी क्षेत्र तथा सरकार मिलकर एक पूर्व निर्धारित अनुपात में करते हैं, जैसे - 40:60

यह कार्य की गुणवत्ता व दक्षता को भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि सरकार 60% वित्त का

भुगतान किस्तों में कार्य गुणवत्ता के आधार पर करती है।

③ BOT : बिल्ट - ऑपरेट - ट्रांसफर मॉडल

इसमें निजी पदाकार अपनी पूंजी लगाकर निम्नलिखित करता है, तथा निर्धारित समय तक अपने निवेश की वसूली तक स्वयं परिचालन (Toll tax) करके सरकार को परिशुद्धि स्थानांतरण कर देता है।

P.P.P. मॉडल में चुनौतियां

- ↳ भू अधिग्रहण
- ↳ कार्य में देरी
- ↳ पथविकलीय हस्तक्षेप
- ↳ निवेश पूंजी का अभाव

अतः उपरोक्त चुनौतियों को ठीक से हल करके देश की तरक्की में P.P.P. मॉडल को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है।

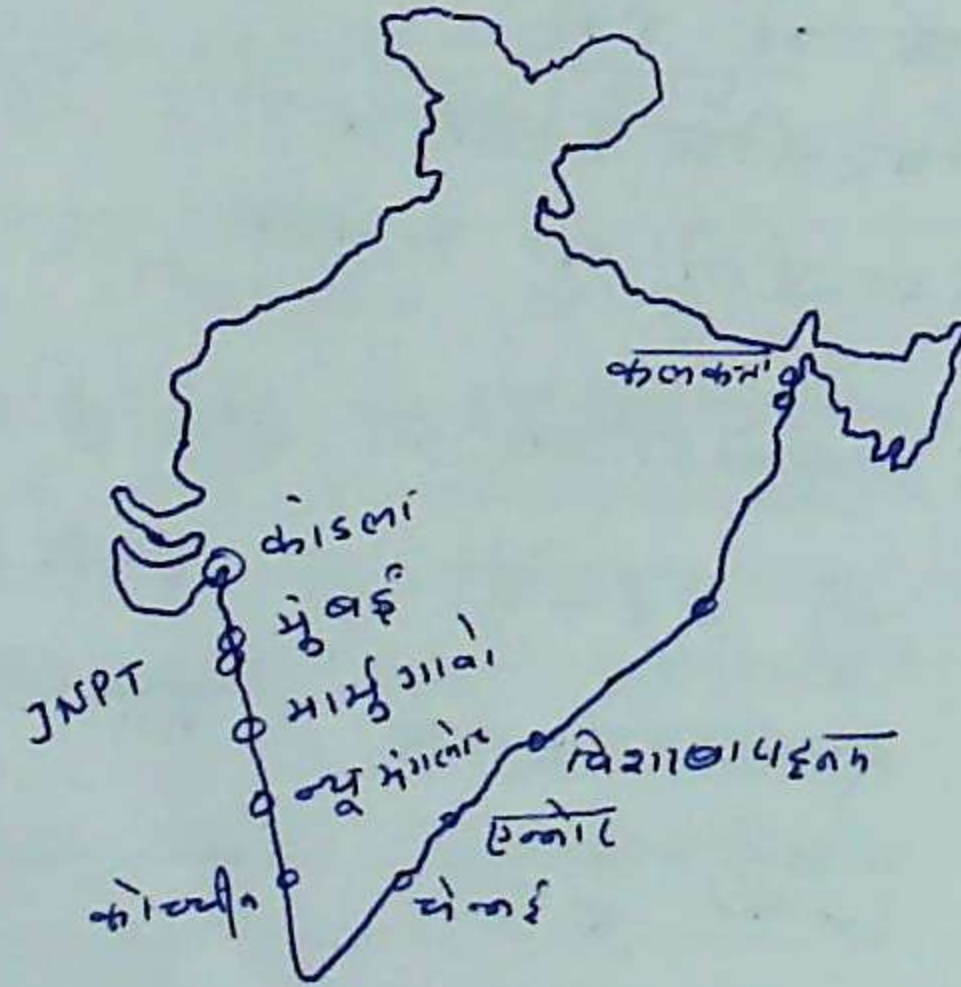
उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

16. बंदरगाह क्षेत्र को न केवल मजबूत करने, बल्कि उसका विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need not just to strengthen but expand, develop, and modernize our port sector. Comment. (250 words) 15

वर्तमान में 13 बंदरगाह तथा लगभग 200 छोटे-छोटे बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाहों में मुंबई, काठला, मारुगावा, चेन्नई, आदि हैं।

हाल के कुछ वर्षों में बंदरगाहों की माल क्षमता तथा टर्न अराउंड समय, दोनों में सुधार हुआ है। पहले के मुकाबले अब प्रति दिन जहाज क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

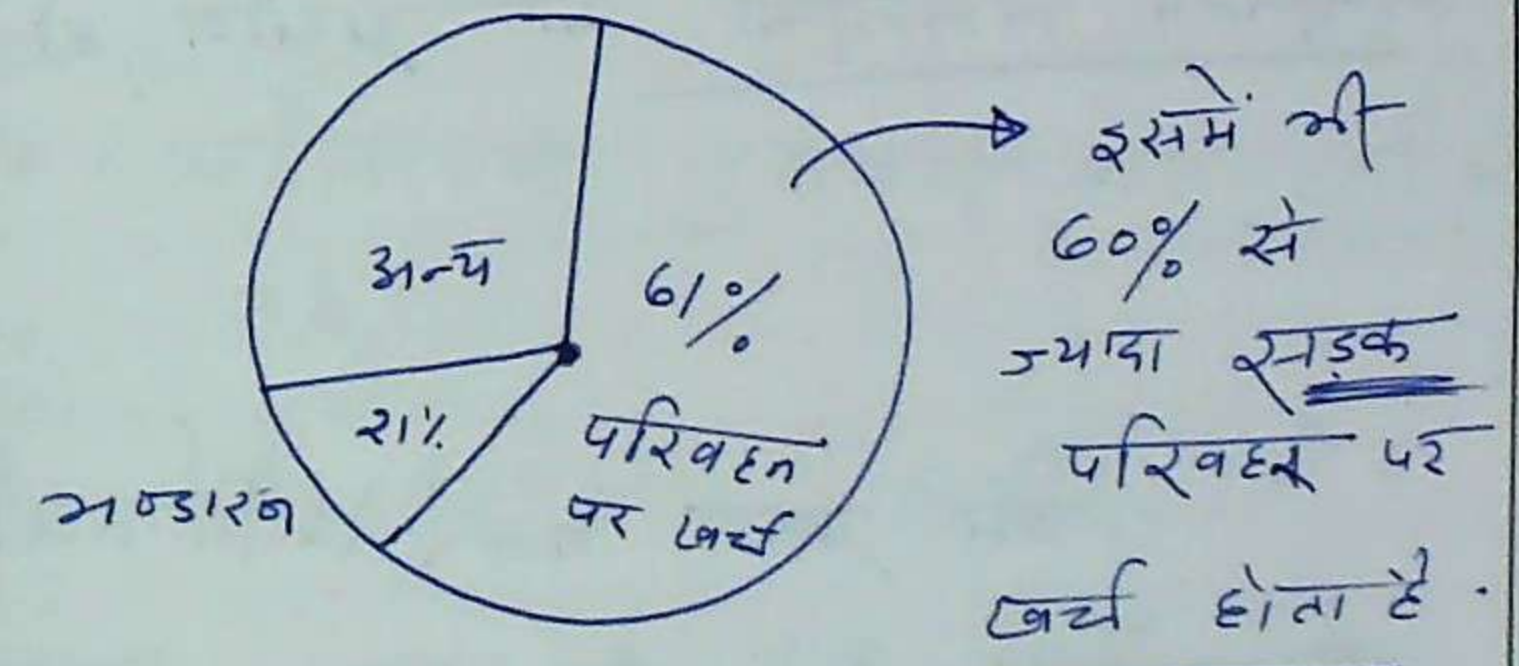


उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

चूँकि समुद्री परिवहन सबसे सस्ता व असुरक्षित परिवहन माध्यम है, तथा विदेशी व्यापार का मुख्य आधार है, इसलिए भारत को बंदरगाहों की क्षमता विकास तथा आधुनिकीकरण पर ध्यान देना आवश्यक है।

→ भारत का लॉजिस्टिक व्यय निम्न प्रकार है।



∴ जल परिवहन क्षमताओं को बढ़ाकर उचित दोहन करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत का आन्तरिक व्यापार का हाल भी बुरा है। मात्र 1% जलमार्ग द्वारा माल परिवहन हो पा रहा है, इस प्रकार यह सर्वविदित है, कि खागरमाला तथा भारतमाला जैसी

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा जलमार्ग क्षमताओं को बढ़ाया जाए, तथा माल हैंडलिंग के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो।

इस प्रकार अन्तर-देशीय तथा अन्तरा-देशीय दोनों ही स्तर पर व्यापार में जलमार्गों का विकास कर न केवल लॉजिस्टिक खर्च कम किए जा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी होगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

17.

भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण और सेवाओं में समर्पित निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिये मेक इन इंडिया पहल अस्थिर-सी हो गई है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

Make in India initiative to encourage manufacturing in India and galvanize the economy with dedicated investments in manufacturing and services is on a slippery slope. Critically analyze.

(250 शब्द) 15

(250 words) 15

वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत जोरशोर से हुई। हालांकि योजना जो देश को कालनिर्मि बगने में निम्न प्रकार से योगदान दिया —

- (1) कई स्वदेशी विनिर्माण कंपनियों की स्थापना हुई
- (2) पहले के मुकाबले नए 'स्टार्ट अप' बढ़े
- (3) फंडिंग आवेदनों की संख्या बढ़ी है परन्तु, यह भी सत्य है कि "मेक इन इंडिया" योजना, कई क्षेत्रों तक अपना प्रभाव नहीं जमा पाई है, जहाँ —

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

⇒ वस्त्र निर्माण उद्योग में कोई विशेष प्रभाव नहीं आया, जो कि भारत को सर्वोच्च रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है।

⇒ बहुत से "स्टार्टअप" कैंड हो रहे हैं। मैंने स्वयं ने वर्ष 2015 में "जैविक खाद्य व डेरी उत्पादों" संबंधी एक एकीकृत उद्यम शुरू किया था, परन्तु विनीय बाधाओं व बाजार की चुनौतियों के चलते इसे बंद करना पड़ा गया।

इस प्रकार से कह सकते हैं, अब धीरे-धीरे 'मेक इन इंडिया' पहल अपनी चमक खो रहा है। जिसके निम्न कारण हो सकते हैं—

- (1) बैंकों की खराब हालत
- (2) निजी निवेशकों की अकृपि
- (3) क्रियान्वयन में कमियाँ

"मेक इन इंडिया" पहल को सफल बनाने के उपाय →.

- (1) बैंक धोरणों को रोका जाये
- (2) कॉराल प्रशासन की जमीनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मूल्यवर्धक प्रशिक्षण दिया जाए।
- (3) एंजेल इन्वेस्टर्स को सरकार प्रोत्साहन दे
- (4) नए उद्यमों के लिए "लीड फंड" की सीमा ₹1 करोड़ तक व्युत्पन्न व्जाज पर की जाए।

इस प्रकार देश को विकसित बनाने के लिए हमें चुनौतियों को चिन्हित कर तुरन्त हल करने की पहली आवश्यकता है, यही हमें 2030 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है।

18. किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि में विकासात्मक पहल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

Developmental initiatives, technology and policy reforms in agriculture are needed for doubling farmers' income. Elucidate. (250 words) 15

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था, तथा इस दिशा में कई संरचनात्मक बदलाव व प्रयास किए भी गए हैं, पर इसीका एक बड़े सामने हैं।

अब तक किए गए प्रयास

- ⇒ कुछ सूचिबद्ध फसलों के MSP में वृद्धि
- ⇒ किसान रेल शुरू
- ⇒ Top योजना
- ⇒ A PM-AASHA योजना के तहत निजी खरीद को बढ़ावा
- ⇒ e-NAM के तहत किसानों के उत्पादों के विपणन में पारदर्शिता लाने की कोशिश। आदि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

परन्तु अग्रेसर उपाय नاکाफी हैं, तथा इसीकात में सर्व सुधारे भी नहीं हो पाये हैं। देश में ऐसे किसानों का जो e-NAM के बारे में जानते होंगे, तक जबकि 85% किसान लघु व सीमांत हैं, जारी हैं, तकनीकी ज्ञान ले सोसा इर हैं।

अतः अब दोरी खासियों से सीधक गए सिरे से निम्न सुधारों की आवश्यकता है —

- (1) किसानों का विश्वास जीता जाए
- (2) उन्हें असोसा दिलाया जाए सरकार राजनीति से इतर उनकी आय को वास्तव में दोगुनी करने हेतु निम्न आधारों पर प्रभावित हैं
- (3) ग्राम पंचायत स्तर पर, इन्टरनर योजनाओं की सार्वजनिक

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

रूप से बनाया जाये।

⇒ लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अवगत कराया जाया।

⇒ प्रत्येक किसान का एक "मेरा किसान - मेरी सरकार" नाम से खाता खोले।

जिले पर क्षेत्रवार तथा जयंतरत अनुसार

दैनिक, मासिक आधार पर अपडेट हो।

ताकि सभी किसानों का असोला जीत

जा उनके व योग्य क्रियान्वयन

में कौताही न हो

⇒ ज्यादा उत्पादन की वजाय सुध गुणवत्ता

युक्त सुध प्राकृतिक उत्पादन पर

ध्यान देकर कृषक उत्पादों को

विदेशी बाजारों में अच्छी कीमतों

पर बेचने की नीति पर काम

करने का वक्त आ गया है। इस

प्रकार निश्चित रूप से किसानों की आय

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

19.

भारत अकुशल अनाज प्रबंधन से ग्रस्त है जो खाद्य सुरक्षा को चुनौती देता है। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

India suffers from inefficient grain management which challenges food security. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत बीते कई दशकों से खाद्य आत्मनिर्भर तथा सुदृढ़ नियंत्रित देशों की श्रेणी में है।

इसके बावजूद भारत में कुपोषण तथा सुखमरी की समस्या लगातार बनी हुई हुई। एलिया

जारी "वैश्विक सुखमरी सूचकांक" में भारत को 142 देशों में 100+ का स्थान मिला है, जो बेहद

चिंताजनक व शर्मनाक तो है कि

सूचक ही इस प्रश्न को सोचने

पर मजबूर करता है, कि

आखिर क्यों?

का मुख्य कारण है, "अकुशल खाद्य प्रबंधन"

विगत कृषि वर्ष भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 300 MMT से ज्यादा रहा, परन्तु फिर भी हम ~~सेक~~ लगभग 10 करोड़ भारतीय हर रात भूखे पेट सो रहे हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

खाद्य प्रबंधन में कठिनाइयाँ

⇒ खाद्यान्नों की खरीद मुख्यतया केन्द्रीय एजेंसी FCI करती है; तथा गोदामों तक जाती है, और अगले आदेशों तक गोदामों पर ताला लगा दिया जाता है।

- जिले बहुत सा खाद्यान्न सड़ जाता है।

→ निम्न दरियाई हैंडलिंग

- ⇒ FCI के पास उच्च कोटी के गोदामों की कमी।
- ⇒ कर्मचारियों पर सख्ती से कमी।
- ⇒ परिवहन में अनावश्यक कर्बा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

बेहतर खाद्य प्रबंधन के उपाय

⇒ पूरे देश के खाद्य उत्पादन व खाद्य मांग की बेहतर मैपिंग हो।

⇒ खाद्यान्न उपलब्ध क्षेत्रों को थुनक करी के खाद्य डेफिसिट क्षेत्रों में सीधा भण्डारण।

⇒ जहाँ, जिले स्थानीय क्षेत्रों में खाद्यन्न वितरित होंगे; वहाँ तहसिल स्तर पर आधुनिक तकनीकों से युक्त गोदाम बनाए जायें, तथा राज्य सरकारों को प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दी जाए,

20.

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में औपचारिकरण के विभिन्न लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

It has often been argued that it will take a structural transformation for the unorganized sector to become organized. In this regard discuss the numerous benefits and challenges to formalization.

(250 words) 15

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तथा इन 90% लोगों द्वारा कुल आय का बहुत छोटा 24-25% ही प्राप्त हो पाता है।

असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य है, वे क्षेत्र या कार्यकर्ता जो किसी पंजीकृत संस्था में काम नहीं कर रहे, तथा जिन्हें औपचारिक मूल मूल सुविधाओं की गारंटी भी नहीं मिली हुई हो।

अतः इस प्रकार इनके न कार्य करने के, अथवा न्यूनतम मजदूरी के या छुट्टी के सरकारी नियम होते हैं, ऐसे

50

में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का आर्थिक - सामाजिक शोषण होता है, तथा अनेक कल्याणकारी योजनाओं में लाभ ले भी वंचित रह जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में

रूपान्तरण करके न केवल इनकी क्षमताओं का पूर्ण दोहन किया जा सकता है, बल्कि नई तकनीकों व प्रशिक्षण में भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

⇒ बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र अक्सर मिलेंगे।

⇒ अधिक विधि तथा योजनात्मक ढंग सुविधाएँ भी प्राप्त हो सकेंगी।

51

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

औपचारिकरण में चुनौतियाँ

- ⇒ सूचना का अभाव
- ⇒ अत्यधिक बेरोजगारी का होना
- ⇒ शिक्षा व कौशल की कमी
- ⇒ पंजीकरण में कानूनी कार्रवाई का जटिल होना।
- ⇒ छोटे दुकानदारों, दाने वालों आदि द्वारा GST आदि की वजह से पंजीकरण से बचना।

इस प्रकार जाहिर है, कुछ नीतिगत बदलाव करके असंगठित क्षेत्र को धीरे-धीरे संगठित क्षेत्र में बदला जा सकता है।

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)